



मन की बात में पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक को किया याद, बोले...

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस



सुंदरबन की महिलाओं के प्रयासों का उल्लेख

मन की बात में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र की झारखाली की महिलाओं के मैंग्रोव संरक्षण के प्रयासों की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि इनमें कई महिलाएं ऐसी हैं, जिन्होंने बाघ के हमले में अपने पति खोए हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक, इन महिलाओं द्वारा लगाए जा रहे मैंग्रोव गांवों को प्राकृतिक सुरक्षा देने के साथ उनकी आजीविका का साधन भी बन रहे हैं।

138वें एपिसोड में 2016 की सैन्य कार्रवाई

पीएम मोदी ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल को उनकी जन्मशती पर याद किया। उन्होंने कहा कि सिंघल का जन्म 27 सितंबर 1926 को आगरा में हुआ था

और उन्होंने अपना जीवन सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों के लिए समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि आंदोलन में सिंघल की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने इस आंदोलन को दिशा और ऊर्जा देने का काम किया।

मोटेरा सूर्य मंदिर का इतिहास
प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोटेरा

स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मंदिर का निर्माण 1025 ईस्वी में राजा भीमदेव के शासनकाल में हुआ था। उनके अनुसार, 1026 में गजनी के हमले के दौरान मोटेरा मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया था। मोदी ने कहा कि आज मोटेरा अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ देश के पहले सोलर विलेज के रूप में भी

जाना जाता है।

जनगणना में सहयोग की अपील

प्रधानमंत्री ने जनगणना को नागरिकों का राष्ट्रीय दायित्व बताया। उन्होंने कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और बड़ी संख्या में परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने लोगों से जनगणना से जुड़े कार्य में सहयोग करने की अपील की।

संक्षिप्तवार्ता

अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई

अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती रेलवे स्टेशन से एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) से चलने वाली देश की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया।

इस ऐतिहासिक क्षण पर शाह ने साबरमती की भूमि को महात्मा गांधी के आत्मशक्ति और सत्य के प्रयोगों की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि आज इसी साबरमती डिवीजन में पर्यावरण संरक्षण, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ी कई नई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। 1,472 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं से आने वाले दिनों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।

ट्राई के बदलाव पर राघव चड्ढा, अब लोगों को अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में किए बड़े बदलावों के बाद देश के करोड़ों प्रीपैड मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत मिली है। अब टेलीकॉम कंपनियों को 28 दिन के बजाय पूरे 30 दिन की वैलेंडिटी वाले रिचार्ज प्लान पेश करना होगा। इसके साथ ही केवल इनकमिंग और मैसेज की सुविधा चाहने वाले ग्राहकों के लिए बिना डेटा वाले विशेष पैक भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को उतनी ही कीमत पर चुकानी होगी जितनी वे सुविधा ले रहे हैं।

इस महत्वपूर्ण बदलाव पर प्रतिक्रिया देकर भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने देश के प्रीपैड मोबाइल यूजर्स को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर उन्होंने बताया कि उन्होंने मुद्दे को संसद में जोर-शोर से उठाया था। उन्होंने कहा कि यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक जनप्रतिनिधि द्वारा संसद में उठाई गई जनता की आवाज पर सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया।

अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने की मिसाइल-ड्रोन की बौछार

तेहरान।होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जहाजों की सुरक्षित आवाजही सुनिश्चित करने के ईरान के शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज करने के बाद, तेहरान ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा घेरे में चल रहे जहाजों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम एक पोत ईरानी हमले का शिकार बना है, जिससे क्षेत्र में तनाव अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद तेहरान ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है।

सीजेपी की बैठक से पहले आशुतोष रांका सहित कई नेता हिरासत में

गुवाहाटी। गुवाहाटी में काकोरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की पहली क्षेत्रीय बैठक से पहले रविवार को पुलिस ने संगठन के



सह-संयोजक आशुतोष रांका सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सीजेपी के मुताबिक, ये सभी लोग असम सचिवालय के पास प्रस्तावित बैठक में शामिल होने जा रहे थे। संगठन ने बैठक स्थल की ओर जाने वाले रास्ते को रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने से रोक दिया गया।

सीजेपी का कहना है कि बैठक का उद्देश्य असम के लोकल मुद्दों पर चर्चा करना और स्वयंसेवकों को एकजुट करना था। बैठक में राज्य में बाढ़ की स्थिति और संगठन की आगामी गतिविधियों पर भी चर्चा प्रस्तावित थी। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई के कारणों को लेकर फिलहाल कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

सआईआर को लेकर लिया फैसला गलत था, लेकिन हम क्या कर सकते थे?

नई दिल्ली। हैदराबाद सांसद और एसआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन औवैसी ने एक बार फिर मतदाता सूची के एसआईआर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वह शुरूआत से ही एसआईआर के खिलाफ रहे हैं



और इसे बैकडोर एनआरसी मानते हैं। औवैसी ने चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। हैदराबाद में औवैसी ने कहा कि मैं शुरू से एसआईआर का विरोध करता रहा हूँ। मेरा मानना है कि एसआईआर को

लेकर लिया गया फैसला गलत था, लेकिन हम क्या कर सकते थे? सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। औवैसी ने हाल में चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आयोग के फैसले किस तरह लिए गए। उन्होंने कहा कि देश को बताया जाना चाहिए कि कितने फैसले बहुमत से लिए गए? औवैसी ने दो चुनाव आयुक्तों की और से दर्ज आपत्तियों का जिक्र करते हुए पूछा कि अगर कुछ फैसले बहुमत के आधार पर नहीं हुए तो उनकी कानूनी स्थिति क्या होगी?

दिल्ली में एसआईआर की समयसीमा फिर बढ़ी, अब 4 दिसंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

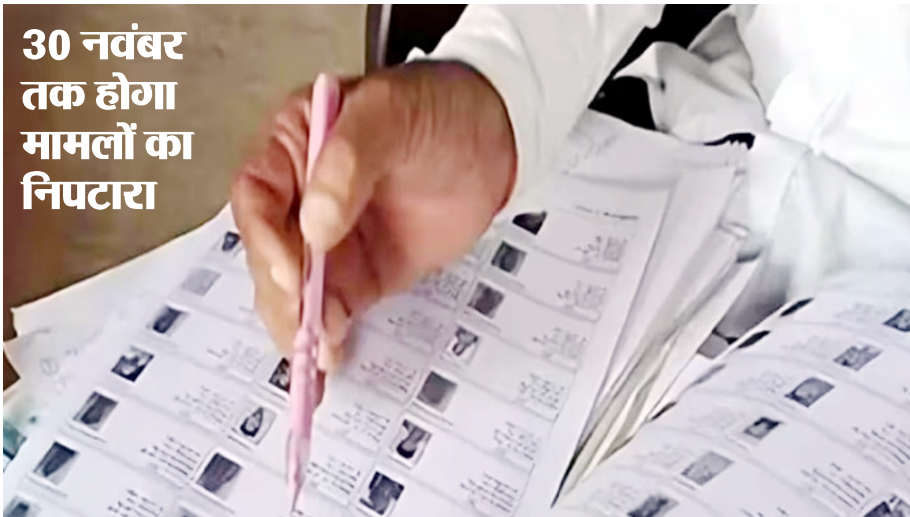
दावे-आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 अक्टूबर तक मौका; बीएलओ घर जाकर ले सकेंगे दस्तावेज

नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है।

चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख 4 नवंबर से बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दी है। इसके साथ ही मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 अक्टूबर तक अतिरिक्त समय दिया गया है। नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड

में विसंगति पाए जाने पर नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया आसान की है। अब ऐसे लोगों को हर मामले में चुनाव कार्यालय जाकर सुनवाई में शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) संबंधित मतदाता के घर जाकर जरूरी दस्तावेज ले सकेंगे। इसके बाद दस्तावेज ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाएंगे, जहां निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) उनके आधार पर फैसला करेंगे।

आयोग के अनुसार, संशोधित कार्यक्रम दिल्ली के



मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से भेजे गए

अनुरोध के बाद जारी किया गया है। सीईओ ने 23 सितंबर को पत्र

भेजकर एसआईआर के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।

चौथी बार बदला एसआईआर का कार्यक्रम

दिल्ली में 14 मई को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद समयसीमा में यह चौथा बदलाव है। शुरूआत में अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी होनी थी। इसके बाद तारीख 19 अक्टूबर, फिर 27 अक्टूबर और 4 नवंबर की गई। अब अंतिम सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

अधिकारियों के मुताबिक, ड्राफ्ट सूची के बाद दोबारा नाम शामिल कराने के लिए नए पंजीकरण के आवेदन अपेक्षाकृत कम आए हैं। इसके अलावा तकनीकी

दिवक्तों और बीएलओ पर काम के दबाव को देखते हुए भी समय बढ़ाया गया है।

पाई गई विसंगतियाँ

ड्राफ्ट सूची में शामिल करीब 97.5 लाख मतदाताओं में से लगभग 33.13 लाख को नोटिस जारी किए गए। इनमें 13.79 लाख मतदाता पुराने एसआईआर रिकॉर्ड से अपना लिंक नहीं जोड़ पाए,

47 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं

31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 1.45 करोड़ पुराने मतदाताओं में से लगभग 47.5 लाख नाम शामिल नहीं किए गए थे। सत्यापन के दौरान इनमें कई मतदाता अनुपस्थित, दूसरी जगह स्थानांतरित, मृत या दुर्लभिकेट पाए गए थे।

कर रहे हैं और फसल भी खड़ी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में इस पर भी गौर करते टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट के 10 फरवरी 2016 के आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने आपत्तियां दाखिल की थीं, लेकिन लंबे समय तक इन पर अधिकारियों ने निर्णय नहीं लिया जिसके चलते अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण अधिग्रहण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। वहीं न तो कच्चा लेने का विश्वसनीय प्रमाण है और न याचिकाकर्ताओं को मुआवजा दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पुराने और नए कानून के अनुसार नहीं होने पर समाप्त हो चुकी है।

रामप्रसाद ने हलफनामा देकर कहा था कि उन्होंने कुमेडी की जमीन पर कच्चा लेने की कार्यवाही नहीं देखी और उनसे दूसरे स्थान की जमीन के संबंध में हस्ताक्षर कराए गए थे। हाईकोर्ट ने इस बयान को महत्वपूर्ण मानते अपने फैसले में कहा कि जब पंचनामा के स्वतंत्र गवाह ने ही तथ्यों से इनकार किया और याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर भी उस पर नहीं हो तो उसे निर्विवाद साक्ष्य नहीं माना जा सकता। ऐसे पंचनामा को कच्चा साबित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। वहीं कोर्ट ने यह भी माना कि रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता जमीन पर खेती

34 साल से चली आ रही ग्राम कुमेडी जमीन अधिग्रहण कार्यवाही निरस्त



मुआवजा नहीं मिला। वहीं, जबकि सुनवाई दौरान आइडीए ने दावा किया कि मुआवजा राशि जमा की जा चुकी थी और 2003 व 2005 में जमीन का कच्चा भी लिया गया। आइडीए द्वारा उक्त जमीन का कच्चा लिए जाने का यह विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका था जहां सुनवाई दौरान आइडीए के द्वारा पेश कथित कच्चा पंचनामा के गवाह

अंबादास कोठारी की सर्वे नंबर 36 की करीब 15 एकड़ जमीन का है जिसे आइडीए की स्कीम 139 में शामिल करने के लिए आइडीए ने 21 मई 1997 को योजना बनाने का प्रस्ताव पारित किया और 7 मई 1999 को ड्राफ्ट स्कीम प्रकाशित की तथा उसके बाद 3 अक्टूबर 2002 को अधिसूचना जारी कर आपत्तियों की सुनवाई पश्चात भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 23 नवंबर 2004 को अर्वाइड पारित किया। इसे लेकर ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कोर्ट को बताया गया कि उन्हें आपत्ति रखने का अवसर नहीं मिला और आज तक

इन्दौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस संदीप एन. भट्ट की एकल पीठ द्वारा दिए एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद आइडीए के हाथ से लगभग 100 करोड़ की जमीन निकल गई। कोर्ट ने फैसला सुनाते करीब 34 साल से चली आ रही इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) की स्कीम-139 के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को निरस्त कर याचिका दायर करने वाले जमीन मालिकों को जमीन का उपयोग करने की स्वतंत्रता दे दी। मामला उज्जैन रोड स्थित सांवर तहसील के ग्राम कुमेडी स्थित पुष्पाबाई कोठारी, घनश्यामदास और उनके पिता

संपादकीय

हिमाचल से देश की उड़नपरी

जाहिर तौर पर अंकतालिकाओं के जिन शिखरों को सीमा ने छुआ, उनमें गर्व के कई क्षण तथा संभावनाओं के कई पल देखे गए हैं। चंबा के छोटे से गांव रेटा से निकली यह धावक आज भारतीय खेलों के इतिहास में अगर अपना नाम चमका रही है, तो यह हिमाचली बच्चों की उत्कंठा का नया सम्मोहन भी है। जिस प्रदेश में अभिभावक बच्चों को लोरियों में भी डाक्टरी और इंजीनियरिंग के पाठ पढ़ाते हों, वहां एक बच्ची अपने जीवन की तमाम वर्जनाओं से बाहर निकल कर खलों में करियर खोजती है। इस जीत में ग्रामीण और पिछड़े परिवेश से संबंधी मां का भी बेहतरीन योगदान है, जिसने अपनी खाली मिलकीयत में देश के लिए प्रतिभा का खजाना भर दिया। सीमा कुमारी के साथ कई कहानियां और तमगे जुड़े हैं, लेकिन बीसवें एशियाई गेम्स के ट्रैक पर जब वह भारतीय तिरगे को पदक के साथ उठाती है, तो यह कहानी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। हिमाचली खेलों में वैसे भी बेटियों का योगदान बढ़ रहा है। सिरमौर की हॉकी खिलाड़ी सीता गोसाईं के नाम के साथ जुड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का जिक्र प्रेरणादायक रहा है, जो भारतीय महिला टीम की कप्तान च चयनकर्ता रही है। भारतीय क्रिकेट टीम में रेणुका सिंह और सुषमा वर्मा का योगदान सारे देश को गौरवान्वित करता रहा है।

एशियन गेम्स में महिला कबड्डी का उल्लेख चार हिमाचली खिलाड़ियों की मौजूदगी में दर्ज हो रहा है। टीम की कप्तान पुष्पा राणा के अलावा रितु नेगी, ज्योति तथा भावना हिमाचल से संबंध रखती हैं। कबड्डी को नया आयाम देने में भी साईं छात्रावास का अहम योगदान है। इस तरह धर्मशाला के प्रणिण में हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन की अकैडमी तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के छात्रावास ने राष्ट्र को यह बताया कि पहाड़ की प्रतिभा को सिर्फ एक दिशा चाहिए, बाकी यह पर्वतीय नदी की तरह सागर ढूँढ लेगी। जाहिर है खेल वातावरण में पिछले कुछ सालों में हिमाचल के प्रयास सफल रहे। वर्तमान सरकार नादौम में एक बड़ा खेल परिसर बना रही है, जबकि अन्य कई प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। विडंबना यह भी रही कि पिछले दस साल से घोषित हाई अल्टीच्यूड खेल परिसर तथा स्वीकृत राष्ट्रीय खेल छात्रावास धर्मशाला में नहीं बन सका। इतना ही नहीं, प्रदेश के ऐतिहासिक व पारंपरिक मैदानों का दायरा सिकुड़ रहा है। सुजानपुर का मैदान कई कार्यालयों ने घेर लिया है, लेकिन बाकी बचे स्थान पर घास को भी चैन से उगने नहीं दिया जा रहा है। कई अन्य स्थानों पर मैदान तो तो पार्किंग स्थल साबित होते हैं या उनका रखरखाव होता ही नहीं। ऐसे में जबकि सीमा कुमारी साबित कर रही है कि हिमाचल एथ्लैटिक्स में देश को मैडल ला सकता है, तो प्रदेश के खेल विभाग को अपनी चयन प्रक्रिया के साथ उम्मीदों के सशक्त कदम उठाने होंगे।

टकराव के बीच अमेरिका- चीन मिलन के कूटनीतिक समझौते

विश्व राजनीति में अमेरिका और चीन के संबंध इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहां टकराव और संवाद दोनों साथ-साथ दिखाई दे रहे हैं। एक ओर दोनों देश व्यापार, तकनीक, ताइवान, दुर्लभ खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक प्रभाव के विस्तार को लेकर एक-दूसरे के सामने खड़े हैं, तो दूसरी ओर आर्थिक हित उन्हें बातचीत की मेज पर भी ला रहे हैं। यही विरोधाभास आज के बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी तस्वीर है। अमेरिका और चीन की हालिया नजदीकी को केवल मित्रता के रूप में देखना जितना गलत होगा, उतना ही इसे महज दिखावटी कूटनीति मान लेना भी उचित नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि दोनों महाशक्तियां यह समझ रही हैं कि लगातार बढ़ता टकराव किसी एक पक्ष के हित में नहीं है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने का असर केवल वाशिंगटन और बीजिंग तक सीमित नहीं रहला, बल्कि उसका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखलाओं, निवेश और विकास की गति पर पड़ता है।

यही कारण है कि तीखे बयानों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद संवाद के दरवाजे खुले रखे जा रहे हैं। अमेरिका अपनी आर्थिक और तकनीकी बढ़त को सुरक्षित रखना चाहता है, जबकि चीन अपने औद्योगिक विस्तार, निर्यात बाजार और तकनीकी विकास के लिए स्थिर अंतरराष्ट्रीय वातावरण चाहता है। दोनों के हितों में टकराव है, लेकिन उनकी आर्थिक आवश्यकताएं उन्हें एक-दूसरे से पूरी तरह अलग होने की अनुमति नहीं देती।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा केवल व्यापार तक सीमित नहीं रह गई है। तकनीक इस संघर्ष का नया केंद्र बन चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत विनिर्माण और दुर्लभ खनिज जैसे क्षेत्र अब आर्थिक विकास के साथ-

साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं। अमेरिका चीन की तकनीकी क्षमता और औद्योगिक विस्तार को लेकर सतर्क है, वहीं चीन अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंधों को अपने विकास के रास्ते में बाधा के रूप में देखता है।

इसके बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत का जारी रहना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों के बीच रणनीतिक अविश्वास समाप्त हो गया है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि दोनों देश अपने मतभेदों को नियंत्रित रखने और उन क्षेत्रों में समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां परस्पर हित जुड़े हुए हैं।

ताइवान का मुद्दा इस रिश्ते की सबसे संवेदनशील परीक्षा है। व्यापार और आर्थिक मामलों में समझ विकसित हो सकती है, लेकिन ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन की रणनीतिक सोच में मूलभूत अंतर मौजूद है। इसी तरह दक्षिण चीन सागर, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक प्रभाव के विस्तार को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद आसानी से समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए वर्तमान नजदीकी को स्थायी दोस्ती की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी।

असल में अमेरिका और चीन के संबंधों में एक नई तरह की कूटनीति दिखाई दे रही है। प्रतिस्पर्धा के साथ सह-अस्तित्व की कूटनीति। दोनों देश एक-दूसरे के प्रभाव को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन पूर्ण टकराव से भी बचना चाहते हैं। वे व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन रणनीतिक निर्भरता कम करना चाहते हैं। वे संवाद चाहते हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी हितों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं।यही स्थिति आने वाले समय की विश्व राजनीति को भी प्रभावित करेगी। यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव नियंत्रित रहता है तो वैश्विक बाजारों को कुछ स्थिरता मिल सकती है। इसके विपरीत यदि शुल्क युद्ध फिर तेज होता है तो उसका असर विकासशील देशों पर भी पड़ेगा। महंगाई, आपूर्ति श्रृंखला और निर्यात बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है।

भारत के लिए इस बदलते समीकरण को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, वहीं चीन भारत का पड़ोसी और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में भारत के लिए किसी एक शक्ति-गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

राहुल गांधी के साथ चलते हुए

की बात सुनते कम हैं। वे सर्वालों के जवाब नहीं देते, कोई हिसाब नहीं देते।

राहुल गांधी लोगों के साथ पैदल चलते हुए कम बोल रहे हैं और देश के लोगों की बात अधिक सुन रहे हैं। राहुल गांधी लोगों को फिर उस पागड़की पर वापस ला रहे हैं जिस पर साथ चलते हुए आपस में सवाल उठाकर उनके जवाब खोजे जाते हैं और जो असहमत है उसका भी सम्मान किया जाता है। जो लोग देश के दूर-दराज इलाकों में जीवन काट रहे हैं और इस यात्रा से सीधे नहीं जुड़ पा रहे, वे भी मन ही मन राहुल गांधी के साथ इस उम्मीद से भरकर चल रहे होंगे कि देश में प्रेम की पागड़ियां पर सबके साथ चलने और जीवन गुजारने के दिन अब जरूर लौटेंगे और नकरत की उड़ती धूल शान्त होगी।

असहनीय रूप से अभद्र और सत्ता की भूख से भरे राजनीतिक परिदृश्य में जहर-बुझे तौर सहते हुए राहुल गांधी की उपस्थिति को हमारे देश के वे करोड़ों संवेदनशील लोग अपने अहसास में जरूर महसूस कर पा रहे होंगे जो विभाजनकारी राजनीतिक मानसिकता को पसंद नहीं करते हैं। देश में ऐसे संवेदनशील लोगों का आज भी बहुमत है जो किसी के

बांटने से बंटने को तैयार नहीं। यही लोग राहुल गांधी के राजनीतिक धीरज को परख होंगे।

राहुल गांधी का यह धीरज हमारे काम आ सके, इसके लिए लोगों को जात-पात के भेद और मतान्ध कट्टरता से अपने आपको मुक्त करना होगा। जनसमर्थन पाकर उसकी राजनीतिक सौदेबाजी करने वाले बिकाऊ प्रतिनिधियों को त्यागना होगा। अप्रुथयता, वैचारिक कट्टरता और सत्ता का लोभ ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा हैं। सबको मिलकर इन बाधाओं को हटाना होगा। लोकतंत्र अपनी विफलताओं से ही सीखकर आगे बढ़ता आया है। हमें इन बाधाओं को हटाने के लिए अपने समय के सत्याग्रह की रचना करके नये विकल्प को गढ़ना होगा।

राहुल गांधी राजनीति की जमीन पर नयी धान रोपने की उम्मीद से भरकर भारत की राजनीति के उन कुल-देवताओं की यादों में खोये हुए लग रहे हैं जिनने बिना किसी भेदाभाव के सबके घर तक स्वतंत्रता का प्रभात और भरपेट पाठ पहुंचाने का पराक्रम किया था। भारतीय राजनीति के कुल-देवता तो महात्मा गांधी ही हैं जिन्होंने सबको जात मेहनत का त्रात साधने

लोकतंत्र में चुनाव केवल मतदान की प्रकिया नहीं

है। यह उस मरोसे का नाम

है, जिसके आधार पर एक

जागरिक यह मानता है कि

उसका वोट सुरक्षित है,

मतदाता सूची में उसका नाम

निष्पक्ष तरीके से दर्ज है और

चुनाव करने वाली संस्था किसी

ढाबा, पक्षपात या मनमानेपन

से मुक्त होकर काम कर

रही है। इसलिए निर्वाचन

आयोग की विश्वसनीयता पर

उठने वाला हर सवाल महज

राजनीतिक विवाद नहीं होता।

वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की

बुनियाद से जुड़ा प्रश्न बन

जाता है।

हाल में निर्वाचन आयोग के भीतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंह संक्षु तथा विवेक जोशी के बीच कथित मतभेदों को लेकर सामने आई रिपोर्ट ने इसी कारण असामान्य चिंता पैदा की है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने पिछले दस महीनों में आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दे पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें नर मतदाताओं के पंजीवन, मतदाता सूची से नाम हटाने, चुनावी डेटा तक पहुंच और आईटी व्यवस्था जैसे गंभीर विषय शामिल बनाए गए हैं। आयोग ने दूसरी ओर इन मतभेदों की व्याख्या अन्ना तरीके से की है और कहा है कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति से हुए तथा ऐसी टिप्पणीयां विचार-विमर्श की प्रक्रिया का हिस्सा थीं। यही वह बिंदु है जहां से असली सवाल पैदा होता है—यदि सब कुछ सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है तो फिर उन आपत्तियों, उनके जवाब और अंतिम निर्णय की प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से स्पष्ट क्यों न हो? यहां किसी रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन उन्हें केवल राजनीतिक आरोप कहकर खारिज कर देना भी पर्याप्त नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का सबसे मजबूत आधार यही है कि वह कठिन सर्वालों का सामना तथ्यों और दस्तावेजों के साथ करे।

सबसे गंभीर प्रश्न मतदाता सूची से जुड़ा है। चुनाव में उम्मीदवार हर-जीत सकता है, राजनीतिक दल स्ता में आ-जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची

में किसी योग्य नागरिक का नाम न होना सीधे उसके संवैधानिक अधिकार को प्रभावित करता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दो निर्वाचन आयुक्तों ने मतदाता पंजीवन के फॉर्म-6 में किए गए बदलाव पर आपत्ति दर्ज की थी। उनका तर्क था कि वैधानिक प्रावधानों से जुड़े फॉर्म में बदलाव के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीक और डिजिटल व्यवस्था अब चुनावी प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मतदाता सूची का डिजिटल प्रबंध सुविधा बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ जवाबदेही भी उतनी ही बढ़ती चाहिए। यदि किसी स्तर पर जांचदेखर किसी अधिकारी के निर्णय को स्वीकार नहीं करना, किसी योग्य मतदाता का नाम अटक जाता है या केंद्रीय स्तर की तकनीकी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर लिए गए वैधानिक निर्णय को प्रभावित करती है, तो उसके लिए स्पष्ट जवाबदेही तय होनी चाहिए। रिपोर्ट में गोवा के 97 मतदाताओं से जुड़ा ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें स्थानीय स्तर पर पाठता स्वीकार किए जाने के बावजूद सौचदेखर संबंधी समस्या का उल्लेख किया गया। यही वजह है कि चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी गलती जैसे शब्द भी हल्के में नहीं लिए जा सकते। बैंकिंग व्यवस्था में गलत खाते में पैसा चला जाए तो उसे तकनीकी बग्ट कहा जा सकता है और सुधार की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन चुनाव में किसी योग्य नागरिक का वोट देने का अवसर निकल जाए तो वह गलती अगले चुनाव तक सुधरने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। चुनावी अधिकार सम्यबढ़ होता है।

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी यही कसीटी लागू होनी चाहिए। मतदाता सूची को साफ-सुभरा और अव्यत रखना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। मृत, स्थानांतरित, देहाए गए या आगर नाम हटाना लोकार्गनिक प्रक्रिया को मजबूत करता है। लेकिन येच मतदाता का नाम हटाने की आशंका भी उतनी ही गंभीर है। पश्चिम बंगाल के मामले में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एसआईआर के दौरान हटाए गए 27.16 लाख नामों में से 22 लाख से अधिक मतदाताओं ने बहाली के लिए अपील की। इस आंकड़े का अर्थ यह नहीं कि हर हटाया गया नाम सही था या हर अपील स्वीकार की जानी चाहिए। इसका सीधा अर्थ केवल इतना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साब एक मजबूत, आसान और सम्यबढ़ अपील व्यवस्था भी अनिवार्य है। नागरिक को यह पता होना चाहिए कि उसका नाम क्यों हटाया गया, निर्णय किस अधिकारी ने लिया, उसके पास कौन-से दस्तावेज होने चाहिए और उसकी शिकायत का अनिश्चितपरा काय तब होगा।

निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद का मुद्दा भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तीन संसदीय आयोगों में असहमति अपने आप में लोकतंत्र विरोधी बात नहीं है। बल्कि किसी भी संस्थागत व्यवस्था में सहमति वस्थ्य विचार-विमर्श का हिस्सा हो सकती है। कानून भी मतभेद की स्थिति में बहुमत से निर्णय की व्यवस्था करता है। 2023 के कानून की 18 के अनुसार आयोग का काम जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से होना चाहिए और मतभेद

होने पर बहुमत का निर्णय लागू होता है। समस्या असहमति नहीं, बल्कि यह संदेह है कि क्या सभी सदस्यों को निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त जानकारी और अवसर मिल रहा है। यदि वो अनुकूल वह लिखित रूप से दर्ज करते हैं कि कुछ फैसले उनकी जानकारी या स्वीकृति के बिना आयोग के नाम से जारी हुए, तो संस्था के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है कि वह रिकॉर्ड सामने रखे और प्रक्रिया स्पष्ट करे। इससे न केवल आरोपों का जवाब मिलेगा, बल्कि आयोग की अपनी प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी। यह भी याद रखना चाहिए कि निर्वाचन आयोग को सामान्य सरकारों विभाग नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 न उसे चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, निदेशन और नियंत्रण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे है। इसलिए उसकी विश्वसनीयता किसी एक सरकार, दल या चुनाव से बड़ी है। आज सत्ता पक्ष को आयोग पर भरोसा हो और कल विपक्ष को—ऐसी संस्थागत विश्वसनीयता ही उसकी असली पूजी है।

राजनीतिक दलों के लिए भी यह समय आत्मचरम का है। चुनाव विचार पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन हर आरोप को प्रामाण, रस्ताखेज और तथ्य के साथ सामने रखना जरूरी है। दूसरी ओर आयोग के लिए भी केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि आरोप निराधार हैं। जनता को यह समझना होगा कि प्रक्रिया क्या थी, निर्णय कैसे हुआ और आपत्तियों का निपटारा किस तरीके से किया गया। विश्वास मानने से नहीं बनता, प्रक्रिया से बनता है। पारदर्शिता उसका सबसे मजबूत आधार है। इसलिए इस पूरे विवाद का रास्ता राजनीतिक

बयानबाजी से नहीं, बल्कि संस्थागत स्पष्टता से निकलेगा। आयोग को महत्वपूर्ण निर्णयों, आंतरिक आपत्तियों और उनके निपटारे की प्रक्रिया के बारे में जितना कानून अनुमति देता है, उतनी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। मतदाता सूची से जुड़े मामलों में ऑडिट होना, जिम्मेदारी और लोगों की व्यवस्था और स्पष्ट होनी चाहिए। तकनीकी प्रणालियों की स्वतंत्र सुरक्षा और प्रक्रिया संबंधी समीक्षा भी समय-समय पर होनी चाहिए। आखिर सवाल किसी एक व्यक्ति की प्रिष्ठि का नहीं है। सवाल उन नागरिक के भरोसे का है, जो मतदान केंद्र पर पहुंचकर वह उम्मीद करता है कि लोकतंत्र की पूरी मशीनरी उसके एक वोट को ईमानदारी से दर्ज करेगी। निर्वाचन आयोग के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती आलोचना से बचना नहीं, बल्कि आलोचना के बीच अपनी संस्थागत विश्वसनीयता को और मजबूत करना है। अगर आरोप गलत हैं तो तथ्यों से गलत साबित किए जाए। अगर प्रक्रिया में कमियां हैं तो उन्हें सुधारा जाए। और अगर आयोग के भीतर मतभेद है तो उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सामान्य बहस के रूप में पारदर्शी तरीके से संभाला जाए। क्योंकि चुनाव में केवल परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता। उससे पहले वह विश्वास जरूरी होता है कि परिणाम तक पहुंचने का रास्ता निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय था। यही विश्वास लोकतंत्र की असली रीढ़ है—और इसी कसीटी पर आज निर्वाचन आयोग को खुद को जनता के सामने स्पष्ट करना होगा।

लेखक - विनोद कुमार उपाध्याय

नई दिल्ली, सोमवार 28 सितंबर 2026

अमेरिका और चीन के बीच यदि तनाव कम होता है तो भारत के लिए वैश्विक आर्थिक स्थिरता का वातावरण बन सकता है। वहीं यदि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है तो भारत के सामने विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला और निवेश के क्षेत्र में अवसर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन इन अवसरों को हासिल करने के लिए भारत को अपनी उत्पादन क्षमता, तकनीकी दक्षता और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना होगा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और चीन की यह नजदीकी कितने समय तक टिकती है। क्या यह वास्तविक समझ की दिशा में कदम है या केवल तत्काल आर्थिक दबावों को कम करने की रणनीति? इसका उत्तर आने वाला समय देगा। दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनना आसान नहीं है। इसलिए किसी एक बैठक या अस्थायी समझौते को स्थायी परिवर्तन का संकेत मानना उचित नहीं होगा।

फिर भी एक बात स्पष्ट है आज की दुनिया में महाशक्तियां भी एक-दूसरे से पूरी तरह कटकर नहीं चल सकतीं। आर्थिक परस्पर निर्भरता, वैश्विक व्यापार, तकनीकी विकास और साझा चुनौतियां उन्हें संवाद के लिए मजबूर करती हैं। यही कारण है कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव के बावजूद बातचीत का सिलसिला जारी है।

अमेरिका और चीन की वर्तमान नजदीकी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि विश्व राजनीति अब केवल शक्ति प्रदर्शन से नहीं, बल्कि शक्ति और आवश्यकता के संतुलन से संचालित हो रही है। दोनों देश प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन एक-दूसरे की आर्थिक और वैश्विक भूमिका की अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए इस नजदीकी को दोस्ती या दुश्मनी के पुराने पैमाने पर देखने के बजाय बदलती विश्व व्यवस्था के संकेत के रूप में समझना चाहिए। आने वाले वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों का स्वरूप वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारकों में रहेगा। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह इस बदलते समीकरण में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए आर्थिक और कूटनीतिक अवसरों का अधिकतम लाभ उठाए।

अमेरिका और चीन को नजदीकी इसलिए केवल दो देशों के रिश्तों की कहानी नहीं है। यह बदलती विश्व व्यवस्था की कहानी है। जहां प्रतिद्वंद्विता खत्म नहीं हुई है, लेकिन टकराव को नियंत्रित करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

सौरभ वाण्येय, लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

गांधी जी ने महान लेखक रस्किन का रचा ---

अनू दिस लारस्ट यानी सर्वोदय का पाठ भी पढ़ा जिसे अंग्रेजी में ब्रेड लेबर यानी अपनी रोटी कमाना भी कहा जाता है ---हर आदमी को धरती की तरफ अपने आपको झुकाकर और पसीना बहाकर अपने और सबके लिए रोटी पैदा करना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। श्रीमद्भग्वद्गीता की कहती है कि --- जो यज्ञ किये बिना खाता है वह चोर है। आज यज्ञ का अर्थ यही है कि अपने ईमान की रोटी के लिए जन और जन-प्रतिनिधि एकजुट होकर मेहनत करें।

राहुल गांधी किसानों के साथ पिण्डलियों तक पानी में खड़े होकर राजनीति की बंधा होती जा रही धरती पर लोकतंत्र की नयी धान उगाती की चाहत से भरे लग रहे हैं। राहुल गांधी के चेहरे पर यह आत्म विश्वास झलकता दिख रहा है कि अगर सबको अपने हुनर से देश को सँवारने के अवसर मिल सकें तो जात-पात और गरीब-अमीर के बीच की दूरी अपने आप कम होने लगेगी। फिर देश के साधनों पर कोई व्यक्ति और जाति अपनी भ्रित्कियत का दावा नहीं करेगी ---बहु विश्वासी जन और उनके चुने हुए

प्रतिनिधि ही देश के जल-जंगल-जमीन और जानवरों के संरक्षक कहलायेंगे।

राहुल गांधी देश की नयी उमर की नयी फसल के साथ खड़े दीख रहे हैं। उनकी दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक भारत में पदयात्रा किसी की भुलाये नहीं भूलती, जब वे कड़कती ठण्ड में एक आधे बाँह की टी-शर्ट पहनकर भारत के लोगों के बीच से आते हुए दिखती दे रहे थे।यह साफ दिख रहा है कि राहुल लोग ने सबकी आँख खता है वह चोर है। जमींदारी और दलों के दिलों में प्रेम के लिए वह जगह बनायी है जिसके सहारे ही लोकतंत्र को संभाला जा सकता है। जब तक देश के बहुविश्वासी बहुजन और उनके बच्चे प्रेमपूर्वक अपनी रोजी कमाकर अपने घर नहीं लाँटेंगे,तब तक लोकतंत्र का सुख भोगना सबके लिए कठिन बन रहेगा। इस समय हम भारत के लोग अपने लोकतंत्र में कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी की अनवरत भारत जोड़ी यात्रा हमें संविधान की उद्देशिका में अंकित उन चार संकल्पों --- स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता को देश के जीवन में चरितार्थ करने की याद दिला रही है।

— लेखक- ध्रुव शुक्ल

आलेख

शिक्षा के लिए लिया गया कर्क केवल रकम नहीं होता। वह किसी विद्यार्थी के भविष्य पर लगाया गया भरोसा होता है। बिहार ने इसी भरोसे के साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। उद्देश्य था कि आर्थिक कठिनाई किसी विद्यार्थी की उच्च शिक्षा के रास्ते में बाधा न बने। लेकिन यदि आवेदन करने के बाद महीनो तक विद्यार्थी को केवल ह्राउंडर प्रोसेसह्म का दर्जा मिले, स्वीकृति के बाद भी राशि का इंतजार करना पड़े और पुराने विद्यार्थियों की फीस अटक जाए, तो सवाल केवल किसी योजना की प्रशासनिक गति का नहीं रह जाता। सवाल यह है कि शिक्षा और सरकारी व्यवस्था के बीच भरोसे का रिश्ता कितना मजबूत है।

सांसद सुधाकर सिंह ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की वर्तमान स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़े रखे हैं, वे इसी सवाल को सामने लाते हैं। उनके अनुसार बिहार के सभी 38 जिलों में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों के पास कुल 1,37,177 आवेदन पहुंचे हैं। इनमें केवल 14,804 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जबकि 1,22,341 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं। यानी प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक करीब 89 प्रतिशत आवेदन अभी स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा में हैं।

यहां ह्राउंडर प्रोसेसह्म प्रशासन के लिए महज एक स्थिति-सूचक हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी के

लिए इसका अर्थ अलग है। उसके सामने कॉलेज की फीस, अगला सेमेस्टर, परीक्षा फॉर्म, छात्रावास और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्च हैं। उसे यह जानना होता है कि पैसा कब मिलेगा। इसलिए किसी शिक्षा वित्त योजना की सफलता का आकलन केवल इन आधार पर नहीं हो सकता कि कितने आवेदन आए या कितनी राशि स्वीकृत हुई। असली कसीटी यह है कि विद्यार्थी को समय पर पैसा मिला या नहीं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2016 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। योजना के तहत अधिकतम चार लाख रुपये तक शिक्षा ऋण का प्राधान्य किया गया। आर्थिक दौर में बैंक इस योजना के माध्यम से ऋण देते थे, बाद में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की व्यवस्था आई। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 2018 से सामान्य ब्याज दर चार प्रतिशत रही, जबकि उससे पहले यह दस प्रतिशत थी।

योजना का मूल उद्देश्य केवल ऋण देना नहीं था। इसे उच्च शिक्षा में अवसर बढ़ाने और आर्थिक कारणों से पढ़ाई छूटने से रोकने की नीति के रूप में सामने रखा गया था। इसलिए आज सवाल यह नहीं कि योजना मौजूद है या नहीं, बल्कि यह है कि वह अपने उद्देश्य तक कितनी तेजी और विश्वसनीयता से पहुंच रही है। सांसद द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का

दूसरा पहलू भी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार 14,804 स्वीकृत आवेदनों के लिए कुल 442.73 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत हुई है, जबकि 14,016 विद्यार्थियों के लिए 167.28 करोड़ रुपये ही वितरित किए गए हैं। इन आंकड़ों का आधार मानें तो स्वीकृत और वितरित राशि के बीच लगभग 275.45 करोड़ रुपये का अंतर है। स्वीकृत आवेदनों और वितरित आवेदनों में भी 788 का अंतर है। सरकार को इन आंकड़ों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। स्वीकृति के बाद राशि के वितरण में कौन-से चरण बाकी हैं? क्या शिक्षण संस्थानों के सत्यापन की प्रक्रिया लंबित है? क्या दस्तावेजों या तकनीकी प्रक्रिया में कोई बाधा है? या भुगतान किसी अन्य प्रशासनिक कारण से रुका है? सार्वजनिक धन से चलने वाली शिक्षा वित्त योजना में इन सर्वालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी के लिए हास्यीकृत ऋणह्रा और हप्मिली हुई राशिह्रा एक ही बात नहीं है। कॉलेज की फीस स्वीकृति-पत्र देखकर जमा नहीं होती। शिक्षण संस्थान को वास्तविक भुगतान चाहिए। यही वह बिंदु है जहां किसी शिक्षा वित्त योजना की विश्वसनीयता की असली परीक्षा होती है। 27 मई 2026 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी अलग अवधि की एक तस्वीर सामने आई थी। उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,24,359 विद्यार्थियों ने योजना के लिए

आवेदन किया। इनमें 97,580 आवेदन स्वीकृत हुए, लेकिन 46,384 विद्यार्थियों को ही योजना की राशि मिल पाई और 51,156 विद्यार्थी राशि की प्रतीक्षा में थे। दोनों आंकड़े अलग-अलग समय और संदर्भ के हैं, इसलिए कोई जोंडकर भी प्रशासनिक स्थिति का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन दोनों से एक साझा सवाल जरूर उभरता है—आवेदन, स्वीकृति और वास्तविक भुगतान के बीच इतनी बड़ी दूरी क्यों बन रही है?

इसका सबसे ज्यादा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ता है जिनके पास वैकल्पिक आर्थिक संसाधन नहीं हैं। संपन्न परिवार का विद्यार्थी कुछ समय तक फीस का इंतजार कर सकता है या दूसरे स्रोत से भुगतान कर सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थी के लिए कुछ महीनों की देरी भी पढ़ाई जारी रखने और पढ़ाई छोड़ने के बीच का अंतर बन सकती है। इसीलिए पुराने विद्यार्थियों का मामला भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी विद्यार्थी ने योजना के भरोसे किसी संस्थान में प्रवेश लिया और बाद के वर्ष में उसकी फीस का भुगतान रुक गया, तो समस्या केवल एक बकाया बिल की नहीं रहती। संस्था फीस मांगता है और विद्यार्थी सरकार की ओर देखता है। इस बीच पढ़ाई जारी रखने पर अनिश्चिता बढ़ती है। ऐसे मामलों में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जून 2025 से जिन विद्यार्थियों

की फीस लंबित होने की बात कही जा रही है, उनकी संख्या कितनी है, कितनी राशि बकाया है और भुगतान में देरी का कारण क्या है। यदि भुगतान में देरी से किसी विद्यार्थी के नामांकन या परीक्षा से बाधा और संदर्भ के हैं, इसलिए कोई स्पष्ट व्यवस्था ही होनी चाहिए। विद्यार्थियों के मानसिक दबाव को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। फीस, ऋण और भविष्य को लेकर लगातार अनिश्चिता युवा विद्यार्थियों के लिए गंभीर तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए सरकार और शिक्षण संस्थानों को सम्यबद्ध भुगतान के साथ प्रभावी शिकायत निवारण और परामर्श की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

एक दूसरा सवाल उन विद्यार्थियों का है जिन्होंने योजना के शुरुआती वर्षों में बैंक से ऋण लिया था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 2018 से ब्याज दर चार प्रतिशत थी और उससे पहले दस प्रतिशत। शुरुआती वर्षों के ऋणों की ब्याज दर और बकाया को लेकर विद्यार्थियों की ओर से राहत की मांग भी सामने आई थी। इसलिए पुराने ऋणों की स्थिति पर पारदर्शी आंकड़े सामने चाहिए। कितने विद्यार्थियों ने अधिक ब्याज दर पर ऋण लिया है? कितने ऋण खाते बकाया हैं? कितनी राशि मूलधन और ब्याज के रूप में लंबित है? क्या ऐसे विद्यार्थियों के लिए पुनर्गठन या राहत की कोई व्यवस्था है? इन

सर्वालों का उत्तर दिए बिना योजना की पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अब केवल ऋण स्वीकृत करने वाली योजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे सम्यबद्ध ऋण वित्त व्यवस्था में बदलने की जरूरत है। आवेदन के बाद सत्यापन कितने दिनों में होगा, स्वीकृति कितने दिनों में होगी और स्वीकृति के बाद शिक्षण संस्थान को भुगतान कितने दिनों में मिलेगा—इन सभी चरणों की स्पष्ट समयसीमा होनी चाहिए।

सरकार को योजना की जिला-वार स्थिति को सार्वजनिक करनी चाहिए। कितने आवेदन आए, कितने सत्यापित हुए, कितने स्वीकृत हुए, कितने अस्वीकृत हुए और कितने भुगतान की प्रतीक्षा में हैं—इनका नियमित सार्वजनिक विवरण विद्यार्थियों और उनके परिवारों के लिए उपयोगी होगा। केवल ह्राउंडर प्रोसेसह्म लिख देना पर्याप्त नहीं है। यह भी बताया जाना चाहिए कि आवेदन किस चरण में लंबित है और उसके निस्तारण की संभावित समयसीमा क्या है।

सांसद सुधाकर सिंह ने योजना की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग देखें तो इसके केंद्र में उठे तथ्यात्मक सर्वालों का उत्तर सरकार को आंकड़ों के माध्यम से देना चाहिए। लोकतंत्र में किसी योजना की सफलता केवल

सरकारी उपलब्धियों से तय नहीं होती; उसकी पर

संक्षिप्तवार्ता

रिश्वत मामले में एनडीएमसी कर्मों की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 27 सितंबर (वेब वार्ता)। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने रिश्वतखोरी मामले में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के कर्मचारी अजीत की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।विशेष न्यायाधीश पुनीत पाहवा की अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। मामला नोरोजी नगर मार्केट में बिरयानी की रेहड़ी लगाने वाले गौरव मानक की शिकायत से जुड़ा है। इनकी जब्त रेहड़ी छोड़ने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। आरोप है कि एनडीएमसी इंसपेक्टर मुकेश बाबू ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की मांग की थी और यह रकम पालिका सहायक अजीत को सौंपने का निर्देश दिया था।

सीबीआई ने सात सितंबर 2026 को आरोपी अजीत को 19 हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। मुख्य आरोपी मुकेश बाबू अभी फरार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिश्वत की मांग और स्वीकारोक्ति के आरोप अत्यंत गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा, जमानत देने से गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हुआ पौधारोपड़

नई दिल्ली, 27 सितंबर (वेब वार्ता)। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रविवार को मोती बाग के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉजिड एफ ब्लॉक आरडब्ल्यूए के साथ 43वें रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम हुआ।

एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने स्थानीय निवासियों और आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के साथ पौधे लगाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, स्थानीय निवासी और एनडीएमसी अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर अटल आदर्श स्कूल प्राइमरी, मोती बाग परिसर में भी पौधे लगाए गए। स्कूल की प्रधानाचार्यां ने भवन की मरम्मत, सफेदी, बंदरों से बचाव और सीवेज की समस्याएं बताईं। चहल ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण कर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पहुंचकर जमीनी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना जन-केन्द्रित सुशासन का हिस्सा है।

गीतों-किस्सों से बंधी समां

नई दिल्ली, 27 सितंबर (वेब वार्ता)। त्रिवेणी कला संप्रम में शनिवार को श्री आर्ट्स क्लब और काल्यायनी ने दास्तान-ए-खुशी का मंचन किया। लेखक निधिकान्त पाण्डेय ने किस्सों और गीतों के जरिये खुशी के उन पलों को मंच पर उतारा, जो रोजमरां की जिंदगी में छूट जाते हैं। कहानी के बीच गीत जिंदगी के अलग-अलग रंग दिखाते रहे, देवानंद झा ने बॉलीवुड के लोकप्रिय गीत गाए। आने वाला पल जाने वाला है जैसे गीतों ने दर्शकों को यादों के सफर पर पहुंचाया। निधिकान्त ने बताया कि खुशी बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि रिश्तों और छोटे पलों में भी मौजूद है। संगीत अधीर दास, अमित कुमार और जीतू नादान ने संभाला, जबकि रजनीश गौतम ने प्रकाश व्यवस्था की। सोहेला कपूर और अनुराधा दर द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुआ।

मिशन ग्रीन दिल्ली से बड़ी हरियाली, प्रदूषण नियंत्रण में मदद : प्रवीण निमेष

नई दिल्ली, 27 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार के ह्यमिशन ग्रीन दिल्लीह्द अभियान के तहत 70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पूरा होने पर गोकुलपुर विधायक सभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी प्रवीण निमेष ने इसे दिल्ली को हरा-भरा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि अभियान से हरियाली बढ़ाने के साथ प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। प्रवीण निमेष ने बताया कि बड़े पौधारोपण अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2026 को वन महोत्सव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने अभियान को आगे बढ़ाया और इसमें आम नागरिकों के साथ विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और आरडब्ल्यूए को भी शामिल किया।

उन्होंने बताया कि नागरिकों ने स्लॉट बुक कर 3.56 लाख पौधे लगाए। दिल्ली के रिज क्षेत्रों में करीब 25 लाख पौधे लगाए गए, जिनमें मध्य रिज, डीडीए रिज और दक्षिण रिज क्षेत्र शामिल हैं।

विश्व पर्यटन दिवस पर दौड़ी दिल्ली, 1,500 से अधिक धावकों ने लिया हिस्सा

नई दिल्ली, 27 सितंबर (वेब वार्ता)। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित गांधी दर्शन, राजघाट में 17वीं चैम्पियंस रन का आयोजन किया गया। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति तथा हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस दौड़ में 1,500 से अधिक धावकों ने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। आयोजन में फिटनेस के साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।

दौड़ को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, खेल जगत से जुड़ी हस्तियां, फिटनेस प्रेमी और विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी मौजूद रहे। एशियाई मैराथन चैंपियन डॉ. सुनीता गोदारा और समिति के निदेशक डॉ. संजीत कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

फिट इंडिया-अतुल्य भारत रहा आयोजन का संदेश

70 लाख पौधरोपण का लक्ष्य पूरा होना बड़ी उपलब्धि : दीपक गाबा

नई दिल्ली, 27 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार के मिशन ग्रीन दिल्ली अभियान के तहत 70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पूरा होने पर भाजपा शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि राजधानी को हरा-भरा बनाने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण आवश्यक है। दीपक गाबा ने कहा कि दिल्ली जैसे महानगर में बढ़ते प्रदूषण और घटते हरित क्षेत्र के बीच पौधरोपण की पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना केवल अभियान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने में सरकारी विभागों के साथ स्थानीय निकायों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आरडब्ल्यूए, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों की भागीदारी रही।

फ्यूचरफोर्ज-2026 में वैश्विक शिक्षा और भविष्य के नेतृत्व पर मंथन

डिजिटल परिवर्तन, उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और युवा नेतृत्व पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वेब वार्ता)। वैश्विक शिक्षा, युवा सशक्तीकरण, डिजिटल परिवर्तन और भविष्य के नेतृत्व को केंद्र में रखकर आयोजित फ्यूचरफोर्ज -2026 में शिक्षाविदों, शोधकताओं, उद्योग विशेषज्ञों और युवाओं ने विभिन्न समकालीन विषयों पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम में भारत के अलावा नेपाल और श्रीलंका के शिक्षाविदों ने भी भाग लिया।

कार्यक्रम के विशेष अंतरराष्ट्रीय कीनोट एवं अकादमिक लीडरशिप राउंडटेबल का विषय हग्लोबल लर्निंग, यूथ एम्पावरमेंट एंड एकेडमिक पैडागॉजीह्द रहा। सत्र में वैश्विक सहयोग तथा शिक्षा एवं क्षमता निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। श्रीलंका स्थित जाफना विश्वविद्यालय के प्रो. सिसेसन सिवानंदमूर्ति ने ह्यडिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सतत व्यावसायिक विकास पर प्रभावह्द विषय पर अंतरराष्ट्रीय कीनोट दिया। उन्होंने डिजिटल परिवर्तन और सतत व्यावसायिक विकास के बीच संबंधों पर विचार रखे।

नेपाल के पोखरा विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नमराज धामी ने वर्चुअल माध्यम से ह्यद्वीसनेशनल ब्रिजजें: उच्च शिक्षा में क्षमता निर्माण के लिए यूरोपीय संघ-दक्षिण एशिया सहयोगह्द विषय पर संबोधित किया। चर्चा में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया। अकादमिक लीडरशिप राउंडटेबल में एफडीडीआई नोएडा की कार्यकारी निदेशक डॉ. मंजु मान, फ़िज्म वर्ल्ड की निदेशक डॉ. अनुभा वालिया तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. वी. शुभमुगुसुंदरम ने भाग लिया। कार्यक्रम में शोध-पत्र प्रस्तुतियों और युवा संवाद का भी आयोजन हुआ। डॉ. पुष्पा कटारिया, अनूप कुमार, डॉ. रतिश गुप्ता, डॉ. बान्या आर्या, गरुवित सिंह, हर्षिता सिंह और आदित्य सिंह सहित प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयों पर अपने शोध एवं विचार प्रस्तुत किए।

अभियान के दौरान करीब 290 पुलिसकर्मियों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया। पुलिस ने बिना हेल्मेट वाहन चलाने, तीन सवारी बैठाने, वाहनों में रंगीन शोशे लगाने, शराब पीकर वाहन चलाने और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। गलत दिशा में वाहन चलाने के



स्वस्थ भारत मजबूत भारत की नींव : विजय गोयल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय गोयल ने कहा कि स्वस्थ भारत ही एक सशक्त और आत्मविश्वासी भारत की नींव है। उन्होंने कहा कि चैम्पियंस रन जैसे आयोजन फिटनेस के संदेश को केवल विचार तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे जनभागीदारी से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ दौड़ते हैं और व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेते हैं, तो इससे विशेष रूप से युवाओं की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने युवाओं से शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

फिट इंडिया-अतुल्य भारत की भावना के साथ आयोजित चैम्पियंस रन में 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ के अलावा 1 किलोमीटर की

फिटनेस एवं पारिवारिक दौड़ आयोजित की गई। गांधी दर्शन परिसर में सुबह से ही धावकों और उनके साथ पहुंचे लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया।

नई दिल्ली, 27 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सड़क की गुणवत्ता को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह और आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के बीच तीखी बहस का मामला सामने आया है। घटना के दौरान एक युवक को थपड़ मारे जाने का वीडियो भी सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने के बाद वहां मौजूद युवक को थपड़ मारा। घटना को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है।

सड़क की गुणवत्ता को लेकर हुआ विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, तिलक नगर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को लेकर निरीक्षण के दौरान मंत्री परवेश साहिब सिंह और स्थानीय विधायक जरनैल सिंह आमने-सामने आ गए। दोनों के बीच सड़क की गुणवत्ता को लेकर तीखी बहस हुई। सामने आए वीडियो में जरनैल सिंह सड़क की ऊपरी परत को हाथ से उखाड़ते दिखाई दे रहे हैं। वह उखड़ी हुई सड़क का हिस्सा मंत्री को दिखाते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं। विधायक का कहना था कि सड़क इतनी कमजोर है कि उसे हाथ से ही उखाड़ा जा सकता है।

वीडियो में दोनों पक्षों के बीच सड़क निर्माण को लेकर बहस होती दिखाई देती है। इस दौरान परवेश साहिब सिंह की ओर से यह कहते हुए सुना जाता है कि लंबे समय से सड़क का निर्माण नहीं हुआ

और अब निर्माण कराया जा रहा है।

इसके जवाब में जरनैल सिंह ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क ऐसी नहीं होनी चाहिए जो थोड़े समय में ही खराब हो जाए। बहस के

देश की ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन स्थलों को जानने-समझने की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

खेल भावना से विकसित होता है आत्मविश्वास

विजय गोयल ने कहा कि भारत केवल ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए से ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां खेल और ऊर्जा की भी समृद्ध परंपरा है। उन्होंने खेलो इंडिया, खिलागे इंडिया की भावना का उल्लेख करते हुए कहा कि

बच्चों और युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने से उनमें अनुशासन, सह भागिता और आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यटन को देश की विविध विरासत और पर्यटन स्थलों से लोगों को जोड़ने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत आने वाले पर्यटक यहां के ऐतिहासिक स्मारकों, आध्यात्मिक केंद्रों, सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से देश की विविधता को करीब से अनुभव करते हैं।

17वें संस्करण में भी दिखा उत्साह चैम्पियंस रन की प्रमुख प्रेरक शक्ति और एशियाई मैराथन चैंपियन डॉ. सुनीता गोदारा ने कहा कि 17वें संस्करण में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 वर्षों से आयोजन का उद्देश्य फिटनेस के संदेश को प्रतिस्पर्धात्मक खेलों से आगे ले जाकर दौड़ को सभी के लिए उत्सव का रूप देना रहा है। उन्होंने कहा कि 1,500

में लेकर मंत्री की ओर बढ़े। वीडियो में वह अन्य लोगों के साथ मंत्री के पीछे जाते दिखाई देते हैं। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ के बीच एक युवक मोबाइल फोन से घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसी दौरान मंत्री और युवक के बीच हाथापाई जैसी स्थिति बनी और मंत्री द्वारा युवक को थपड़ मारे जाने का दृश्य वीडियो में दिखाई देता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, युवक ने आरोप लगाया कि वह विधायक के सामाजिक माध्यम के लिए घटनाक्रम का सीधा प्रसारण कर रहा था।

ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, हिंदू महासभा भवन पर प्रदर्शन



नई दिल्ली, 27 सितंबर (वेब वार्ता)। ग्लोबल वैश्य फेडरेशन, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और अन्य संगठनों ने रविवार को मंदिर मार्ग स्थित हिंदू महासभा भवन के पास धरना-प्रदर्शनकिया।प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को भारत रत्न देने की मांग उठाई।

यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और ग्लोबल वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से मतदाता सूची में किए जा रहे सुधार के लिए ज्ञानेश कुमार के योगदान को सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन में संगठन उनके साथ खड़े हैं। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के साथ विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी रखी गई।

गोयल ने विपक्षी नेताओं द्वारा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों और विरोध पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने

कहा कि चुनाव संबंधी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हैं और इसके लिए पृष्ठभूमि के अनुरोध आयुक्त को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शन में मनदीप गोयल, विनोद गुप्ता, ईश्वर चौधरी, राजेंद्र मितल, जगदीश गोयल, राजकुमार जिंदल, सुमन गुप्ता, दीपक बंसल, दिनेश जिंदल, दीपक गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे।

मिर्च झोककर डिलीवरी कर्मी से लूट, 2 बहनों गिरफ्तार

नई दिल्ली, 27 सितंबर (वेब वार्ता)। बाहरी दिल्ली के बुध बिहार इलाके में डिलीवरी कर्मी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर पासल लट्टने के मामले में पुलिस ने 15 घंटे के भीतर 2 बहनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 लूट गए पासल, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, 25 सितंबर की शाम करीब 7:20 बजे सेक्टर-5, रोहिणी स्थित हनुमान मंदिर के पास डिलीवरी कर्मी पासल लेकर पहुंचा था।

कछुआ तस्करी मामले में मणिवन्नन रिहा, भारत में चलेगी जांच

नई दिल्ली, 27 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली हाई कोर्ट ने थाईलैंड में 840 रेडिफटेड कछुओं की तस्करी के मामले में वांछित मुरुगेसन मणिवन्नन को रिहा करने का आदेश दिया है।

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसे थाईलैंड प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा और मामले की जांच भारत में सीबीआई करेगी।

अदालत ने कहा कि जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मणिवन्नन का प्रत्यर्पण नहीं किया जाना है, तो प्रत्यर्पण आदेश के आधार पर उसकी हिरासत जारी नहीं रखी जा सकती। अदालत ने निर्देश दिया कि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न होने पर उसे तत्काल जेल से रिहा किया जाए।

मणिवन्नन को 6 नवम्बरी 2026 को पटियाला हाउस अदालत ने थाईलैंड प्रत्यार्पित किए जाने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया था। हालांकि, निर्धारित अवधि में

संक्षिप्तवार्ता

पुण्यतिथि पर पिता की स्मृति में 70 बटुक ब्राह्मणों को कराया भोजन

वेब वार्ता, ललितपुर

श्राद्ध पक्ष में पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने की सनातन परंपरा के तहत पत्रकार आलोक चतुर्वेदी ने अपने पूज्य पिता स्व.कैलाश नारायण चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर अन्नदान एवं बटुक ब्राह्मण सेवा का आयोजन किया।



पत्रकार आलोक चतुर्वेदी ने अपने पिता स्व.कैलाश नारायण चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर किया अन्नदान

उन्होंने हनुमान धारा मंदिर परिसर में संचालित महंत श्रीगोपीदासजी वेद विद्या संस्कृति गुरुकुलम पहुंचकर वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे करीब 70 बटुक छात्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्व.कैलाश नारायण चतुर्वेदी का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद गुरुकुल में अध्ययनरत बटुकों को भोजन कराया गया। इस दौरान वैदिक शिक्षा एवं संस्कारों की परंपरा को आगे बढ़ाने में गुरुकुल की भूमिका के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया गया। श्राद्ध पक्ष में अन्नदान और ब्राह्मण सेवा को पितरों के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त करने की परंपरा से जोड़ा जाता है। इसी भावना के साथ आलोक चतुर्वेदी ने अपने पिता की पुण्यतिथि को बटुक सेवा और अन्नदान के रूप में मनाया।

उन्होंने कहा कि पूर्वजों की स्मृति में किए जाने वाले सेवा कार्यों को यदि वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बटुकों की सेवा से जोड़ा जाए तो इससे एक ओर पितरों का स्मरण होता है, वहीं दूसरी ओर वैदिक शिक्षा और संस्कारों की परंपरा को सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों की स्मृति में अन्नदान करने के साथ वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बटुकों की सेवा करना सनातन परंपरा, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का सुंदर माध्यम है।

इस अवसर पर यह संदेश भी दिया गया कि पितरों की पुण्यतिथि, श्राद्ध अथवा अन्य शुभ अवसरों पर श्राद्धलु हनुमान धारा मंदिर स्थित महंत श्रीगोपीदासजी वेद विद्या संस्कृति गुरुकुलम में वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बटुक छात्रों की सेवा में सहभागी बन सकते हैं। इससे अन्नदान के साथ वैदिक शिक्षा और संस्कारों की परंपरा को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

47 करोड़ की लागत से कुशीनगर में एसटीपी स्थापित होगा

वेब वार्ता, कुशीनगर

कुशीनगर जिले के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन केंद्र कुशीनगर में 47 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया जाएगा। प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 40 लाख लीटर सीवरेज से आने वाले गंदे पानी को उपचारित करने की होगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही कार्यदायी संस्था सीएनडीएस निर्माण कार्य शुरू करेगी।

एसटीपी के लिए नेशनल हाईवे के समीप हिरण्यवती नदी के किनारे नगरपालिका की करीब पांच एकड़ खाली भूमि चिह्नित की गई है। परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद नगर से निकलने वाले गंदा पानी वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जा सकेगा। इससे नदी और नालों में सीधे गंदा पानी जाने पर रोक लगेगी और पर्यावरण के साथ भूजल की गुणवत्ता को भी संरक्षण मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि बुद्ध स्थली की ऐतिहासिक व धार्मिक पहचान से जुड़ी हिरण्यवती नदी का आंचल (पानी) मैला होने से बचेगा।

गंडक नदी में बढ़ते डिस्चार्ज से बाढ़ का संकट गहराया

वेब वार्ता, कुशीनगर

कुशीनगर जिले क्षेत्र में गंडक नदी में पानी का डिस्चार्ज बढ़ने से गंडक नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ संकट गहराता जा रहा है। आज रविवार को वाल्मीकि



बैराज से गंडक नदी में छोड़े जा रहे पानी का डिस्चार्ज शनिवार को सुबह 9:15 बजे 4,80000 क्यूसेक रहा। इसम गंडक नदी में पानी का डिस्चार्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार रात एक बजे 3.06 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज था, जो रविवार को भोर चार बजे 3.27 लाख, पांच बजे 3.51 लाख, सुबह सात बजे 4.67 लाख क्यूसेक पहुंच गया। इससे एक दिन पहले शुक्रवार 25 सितंबर को दोपहर एक बजे डिस्चार्ज 95,200 क्यूसेक था। इधर, भैसाह गेज पर शनिवार शाम चार बजे गंडक नदी का जलस्तर 95.55 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु से 55 सेंटीमीटर ऊपर है। डिस्चार्ज में बढ़ोतरी को देखते हुए नदी के जलस्तर में अभी और वृद्धि की आशंका जताई जा रही है।

प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने दुदही नगर पंचायत कार्यालय एवं डिजिटल लाइब्रेरी का किया लोकार्पण

वेब वार्ता, कुशीनगर

कुशीनगर में प्रदेश के कारागार विभाग के मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने आज दुदही नगर पंचायत में नवनिर्मित आदर्श नगर पंचायत कार्यालय एवं वातानुकूलित डिजिटल लाइब्रेरी का विधिवत पूजन-अर्चन के साथ लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी का अवलोकन कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली तथा इसे विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए उपयोगी सुविधा बताया। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री ने उपस्थित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

हरदोई में बारिश का कहर: 7 की मौत, 7 घायल, 30 पशु मरे; 330 मकान प्रभावित

हरदोई। जिले में बीते दिनों से जारी बारिश और अतिवृष्टि ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। 25 से 27 सितंबर 2026 तक जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार अतिवृष्टि से जिले में 7 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं, 30 पशुओं की मौत हुई है और 330 मकान प्रभावित हुए हैं।

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को

देवरिया में सरयू नदी के दक्षिण स्पर पर कटान तेज

देवरिया 27 सितम्बर। देवरिया जिले में बाढ़ का पानी घटते ही सरयू नदी ने देवसिया गांव के दक्षिण स्पर बंधे के पास कटान तेज कर दी है। नदी अब भागलपुर-मईल मुख्य मार्ग के बंधे से महज 50 मीटर की दूरी पर बह रही है। कटान देख ग्रामीणों में दहशत है।

ग्रामीणों को गांव और मार्ग पर संकट का डर सताने लगा है। जुलाई में बाढ़ खंड ने बांस-बल्ली डालकर कटान रोकने की कोशिश की थी मगर जलस्तर घटते ही बांस-बल्ली नदी में बह गई। देवसिया और छित्तपुर के पश्चिमी किनारे से बहने वाली सरयू जलस्तर बढ़ने और घटने, दोनों स्थिति में कटान करती है। ग्रामीणों के अनुसार, पिछले दस वर्षों में नदी सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन काट चुकी है। जुलाई में बाढ़ खंड ने बांस-बल्ली डालकर कटान रोकने की कोशिश की थी मगर जलस्तर घटते ही बांस-बल्ली नदी में बहने लगी। इस संबंध में बाढ़ खंड के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार ने बताया कि कटान रोकने के प्रयास जारी हैं।

अमरोहा गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, 7 दिन में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

वेब वार्ता, अमरोहा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र में हरियाणा की 24 वर्षीय महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के दो सेवारत कर्मियों तथा सीआरपीएफ के दो कर्मियों की कथित संलिप्तता अत्यंत गंभीर है और कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई अपेक्षित है।

आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहतकर ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले

बारिश को लेकर हरदोई में प्रशासन अलर्ट, डीएम-एसपी ने किया स्थलीय निरीक्षण

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। लगातार हो रही बारिश के बीच जनपद में राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर प्रशासन ने सक्रियता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने शनिवार को शहर के विभिन्न संवेदनशील स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर जलभराव, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों को बारिश से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर संचालित कराने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने



सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य किए गए। कई तहसीलों में प्रभावित परिवारों को पंचायत भवन, विद्यालयों और आसपास के सुरक्षित घरों में शिफ्ट कराया गया। प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविरों में

भोजन और राशन की व्यवस्था भी की गई।

शाहाबाद में राहत शिविर सक्रिय

शाहाबाद तहसील में अतिवृष्टि से एक व्यक्ति की मौत हुई, एक पशु की मौत हुई और 28 मकान

तेजी से बढ़ रहे ओरल कैंसर, यूपी में सबसे ज्यादा पाये जा रहे है मरीज

30 से 50 साल की उम्र के 70 फीसदी लोग मुख कैंसर के शिकार



ओरल कैंसर के लक्षण

डॉ अक्षत मलिक ने बताया कि मुंह के ओरल कैंसर के लक्षणों में मुख्यतः मुंह में सफेद या लाल चकता होना, मुंह के अन्दर दाने का उभार होना, एक महीने तक किसी धाव या छले का टीक न होना, गले में छोटी गांठ का होना यह कैंसर के प्रथम स्टेज के लक्षण है जिसे समय रहते ही किचकित्सक को दिखा लेना उचित रहता है।

ने बताया कि अब मुंह के कैंसर के इलाज रोबोट सर्जरी के द्वारा बहुत ही आसानी से किया जा रहा है। इस रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जा चुकी है। ज्यादातर मुंह का कैंसर सेक्सुअल यानी की (एचपीवी)

किसान युवा संसद' में उठा लोकतंत्र और जवाबदेही का मुद्दा, नरेश चौधरी ने की आयोग व प्रशासन की सराहना

वेब वार्ता/ अमरोहा

भारतीय किसान यूनियन (संयुक्त मोर्चा) के बैनर तले रविवार को आयोजित 'किसान युवा संसद' के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने विधायक फार्म हाउस गैंगरेप से जुड़े मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संज्ञान लेने, किसी भी घटना में संबंधित फार्म हाउस मालिक की जिम्मेदारी तय करने तथा सदिग्ध गतिविधियों के अंदेश वाले ऐसे तमाम फार्म हाउसों की जांच और लेखा-जोखा कराने की मांग पूरी होने पर आयोग

एवं जिला प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

भाकियू संयुक्त मोर्चा की औद्योगिक क्षेत्र गजरीला में रविवार को आयोजित 'किसान युवा संसद' की पंचायत में केवल सरकारी नौकरी पर निर्भरता कम कर ग्रामीण आधारित उद्योगों तथा संगठित रोजगार मॉडल से जोड़ने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। बताया गया कि किसान युवाओं को जोड़ने की मुहिम में केवल प्रशिक्षण के आंकड़ों के बजाय चयन, रोजगार और व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं की वास्तविक संख्या को सफलता का मानक



जिलाधिकारी ने वहां चल रहे जल निकासी कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्युत आपूर्ति की स्थिति और बारिश के दौरान सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को विद्युत व्यवस्था

को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

डीएम ने कहा कि बारिश के दौरान विद्युत आपूर्ति से जुड़ी किसी भी समस्या को गंभीरता से लिया जाए। किसी भी

मकान प्रभावित हुए हैं। यहां झोपड़ी में रखा घरेलू सामान भी नष्ट हुआ है।

खिलग्राम में 83 मकान प्रभावित

खिलग्राम तहसील में अतिवृष्टि से न कोई जनहानि हुई और न कोई व्यक्ति घायल हुआ। पशुहानि भी शून्य रही, लेकिन बारिश के कारण 83 मकान प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी रखे गए हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

गौतम, आयोजन सचिव डॉ. अमृता श्रीवास्तव तथा संपूर्ण आयोजन समिति को इस भव्य एवं सफल आयोजन के लिए हृदय से बधाई और धन्यवाद दिया।

30 से 50 साल के लोग हो रहे कैंसर के शिकार
डॉ अक्षत मलिक ने बताया कि 70 फीसदी लोग 30 से 50 साल की उम्र के है जिनमें मुंह का कैंसर का ज्यादा पाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक शोध के मुताबिक एक लाख में 50 लोग ओरल कैंसर का शिकार हो रहे है , खास कर उत्तर प्रदेश में ज्यादा मरीज मुख कैंसर के देखे जा रहे है।

सम्मेलन के अंतर्गत टीएसएच ग्राउंड, कानपुर में एक मैत्री क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया। यह रोमांचक मुकाबला साइनस टाइटन्स और ऑरल टाइटन्स के बीच खेला गया। शानदार प्रदर्शन के लिए ईश्वरंटी विभाग के प्रोफेसर डॉ. निशांत सक्सेना को हार्मन ऑफ द मैचरू घोषित किया गया।

मिथक है। रेडियेशन में अब पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि 90 फीसदी लोग पान मसाला खाने के कारण मुख के कैंसर का शिकार हो रहे है तो वहीं 10 फीसदी लोग दंत से गाल के कट जाने के कारण कैंसर का शिकर हो रहे है। 70 फीसदी कैंसर के मरीज अंतिम स्टेज पर ही आते है। इस दौरान आयोजन अध्यक्ष एवं ईश्वरंटी विभागाध्यक्ष प्रो . (डॉ.) हरेंद्र कुमार

ह्यूमन पैपिलोमावायरस से होता है। उन्होंने बताया कि विदेशो की अपेक्षा भारत में यह वायरस तेजी से फैल रहा है। डॉ अक्षत मलिक ने बताया कि लोगो की भ्रांतियां है कि बायोप्सी कराने से कैंसर बढ़ता है जबकि यह पूरी तरह से

माना जाएगा। इसके अलावा, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और कृषि जैसे सार्वजनिक मुद्दों पर नियमित क्षेत्रीय रिपोर्ट तैयार करने तथा युवावों के दौरान उम्मीदवारों के घोषित रिकॉर्ड के आधार पर तथ्यपरक संवाद स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। 'रोजगार भी, जवाबदेही भी, मजबूत लोकतंत्र भी' और 'युवा जागेगा, गांव बागें बढेगा' के संकल्प के साथ आयोजित उक्त 'किसान युवा संसद' पंचायत में ग्रामीण भारत के भावी राजनीतिक परिदृश्य को नई दिशा देने की घोषणा की गई है।

जिलाधिकाारी ने आपातकालीन सेवाओं की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि आपातकालीन सेवाएं समय से उपलब्ध रहें और अस्पताल का समस्त स्टाफ सक्रिय एवं मुस्तैद रहे। साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवाओं और आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दीपाणी भार्गव, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, उप जिलाधिकारी सदर मयंक कुंडू सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

पित्त की नली में फंसी जटिल पथरी से मिलेगा बिना बड़े ऑपरेशन के छुटकारा

इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सी तकनीक से तोड़ी गई पित्त नली की 2.5 सेमी की पथरी, कैंसर जांच भी होगी सटीक

वेब वार्ता, हररी शंकर शर्मा

कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कालेज के पीजीआई गैस्ट्रोएंट्रॉलजी विभाग में शनिवार को एक विशेष कोलांजियोस्कोपी वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप के दौरान ऐसे जटिल मरीजों का अत्याधुनिक विधि से इलाज किया गया, जिनकी पित्त की नली में दो से ढाई सेंटीमीटर तक की बड़ी पथरी फंसी हुई थी और जो बार-बार ईआरसीपी प्रक्रिया कराने

के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रही थी।

वर्कशॉप में विशेषज्ञों ने कोलांजियोस्कोपी के साथ इलेक्ट्रो-

हाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सी (ईएचएल) तकनीक का प्रयोग करते हुए फंसी हुई पथरी को अंदर ही छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा और फिर ईआरसीपी

के जरिए सफलता पूर्वक बाहर निकाल लिया।

गैस्ट्रोएंट्रॉलजी विभागाध्यक्ष डॉ. विनय कुमार ने बताया कि

कोलांजियोस्कोपी तकनीक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस विधि से मरीजों को पित्त की नली के बड़े और जटिल

टीम को बधाई दी।

क्या है कोलाजियोस्कोपी ?

डॉ. विनय कुमार के अनुसार, कोलांजियोस्कोपी पित्त नलिकाओं की बीमारियों के सटीक निदान और उपचार की सबसे उन्नत तकनीक है। इसमें एक बेहद पतली, लचीली ट्यूब (कोलैंजियोस्कोप) का उपयोग किया जाता है, जिसके आगे हाई-डेफिनिशन कैमरा लगा होता है। इसे पित्त की नलिकाओं में डालकर अंदर की स्पष्ट तस्वीरें ली जाती हैं।

वेस्टइंडीज बोर्ड ने खिलाड़ियों की अनुबंध फीस घटायी



जमेका। क्रिकेट वेस्टइंडीज बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की अनुबंध फीस 25 फीसदी कम कर दी है। बोर्ड के अनुसार अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को सालाना अनुबंध मिलता रहेगा पर उनकी तय फीस पहले के मुकाबले 25 फीसदी कम होगी।वहीं घरेलू खिलाड़ियों को भी अब सात महीने को ही अनुबंध मिलेगा।पैसे की कमी के कारण ही बोर्ड ने पुरुषों की सुपर50 और महिलाओं की टी20 ब्लेज प्रतियोगिताएं रोक दी हैं। क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस डियरिंग ने कहा कि खिलाड़ियों और वेस्टइंडीज प्लेयर्स एसोसिएशन ने वर्तमान हालातों को समझते हुए सहयोग किया है। उन्होंने माना कि फीस में कटौती सही नहीं कही जा सकती पर इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

बोर्ड के अनुसार पुरुषों की सुपर50 और महिलाओं की टी20 ब्लेज प्रतियोगिताओं को इसलिए आयोजित नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि इन्हें आयोजित करने पर काफी खर्च आता है। गौरतलब है कि सुपर50 वेस्टइंडीज की पुरुष एकदिवसीय टीम तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों के लिए अहम मंच रहा है। ऐसे में इसका रुकना विकास और चयन प्रक्रिया पर भी असर डाल सकता है। वहीं अनुबंध राशि कम होने से टीम के अच्छे खिलाड़ी अब विदेशी लीग की तरह भाग सकते हैं। पहले ही उसके कई खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम को छोड़कर दुनिया भर की लीग में खेलते हैं। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज को फरवरी–मार्च 2027 में एकदिवसीय विश्व कप क्वालीफायर खेलना है। टीम 2023 के एकदिवसीय विश्व कप में जगह नहीं बना सकी थी। अब बोर्ड का कहना है कि उसका ध्यान पुरुष टीम को इस क्वालीफायर के लिए तैयार करने पर रहेगा क्रिस डियरिंग के मुताबिक, घरेलू क्रिकेट व्यवस्था पर यात्रा, होटल, मैच और आयोजन से जुड़ा खर्च लगातार बढ़ता गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में केवल घरेलू विमान सेवाओं पर 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किए गए हैं। बोर्ड का कहना है कि मौजूदा आर्थिक दबाव में इस तरह का खर्च उठाना संभव नहीं है।

पीटरसन एकदिवसीय विश्वकप के लिए इंग्लैंड के विशेष सलाहकार बने

लंदन (ईएमएस)। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन को टीम का विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप की तैयारी पर नजर रखेंगे। मौजूद जानकारी के अनुसार, पीटरसन श्रीलंका के खिलाफ होने वाली छह मुकाबलों की श्रृंखला से टीम के साथ जुड़ेंगे। इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 और तीन एकदिवसीय मुकाबले

खेलने हैं। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के दौरों पर भी टीम के साथ काम करेंगे। विश्व कप से पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखलाओं में भी उनकी भूमिका जारी रहेगी।माना जा रहा है कि ने ईसीबी ने पीटरसन को जिम्मेदारी देने के पीछे दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभव को भी अहम कारण बताया है। पीटरसन का जन्म और पालन-पोषण दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और अगला 50 ओवर का विश्व

टेस्ट में सबसे तेज 13000 रन बनाने वाले 5 बल्लेबाजों में दो भारतीय भी शामिल

मुम्बई। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13000 रन बनने वाले विश्व के पांच बल्लेबाजों में दो भारतीय भी शामिल है।

इस विशिष्ट सूची में भारत के सचिन तेंदुकर और राहुल द्रविड़ के अलावा, दक्षिण अफ्रीका के जैक कालिस और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग व इंग्लैंड के जो रूट भी शामिल हैं। सबसे पहले ये उपलब्धि सचिन ने हासिल की थी। सचिन को इस आंकड़े तक पहुंचने में 20 साल और 63 दिन का समय लगा था। उन्होंने साल 2010 में बांग्लादेश के

खिलाफ 163 वें टेस्ट मैच की 266वीं पारी के दौरान सबसे तेजी से 13,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। वहीं इस सूची में दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक्स कैलिस हैं। कैलिस ने 2 जनवरी 2013 को न्यूजीलैंड के खिलाफ केप टाउन में यह उपलब्धि हासिल की। अपने डेब्यू के 17 साल और 19 दिन बाद, 159वें मैच की 269वीं पारी में कैलिस ने 13,000 रनों का आंकड़ा पार किया। इस प्रकार उन्होंने 13000 तक पहुंचने के लिए सचिन से केवल 3 पारियां अधिक खेलीं। इसी सूची में तीसरा नाम



ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तानो रिकी पोंटिंग को है। पोंटिंग ने . 24 जनवरी 2012 को भारत के खिलाफ एडिलेड

ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर अपने 13,000 रन 162वां मैच की 275वीं पारी में पूरे किये। अपने डेब्यू

स्मिथ सहित ये दिग्गज बल्लेबाज शुरुआत में करते थे गेंदबाजी

सिडनी। विश्व क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ सहित कुछ क्रिकेटर ऐसे भी थे जो अपने करियर की शुरुआत में गेंदबाजी करते थे पर संयोग से बल्लेबाज बन गये। किस्मत से बल्लेबाज बने ये खिलाड़ी बेहद सफल रहे और आज इनकी मिनती दिग्गज बल्लेबाजों में होती है। स्मिथ की बात करें तो वह अपने करियर की शुरुआत में मुख्य रूप से एक लेग–स्पिनर थे। वह निचले क्रम में थोड़ी–बहुत बल्लेबाजी कर लेते थे। साल 2010 में जब उनका अंतरराष्ट्रीय डेब्यू हुआ, तब वह आठवें या नवें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे . बाद में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी तकनीक पर कड़ी मेहनत की और आज स्मिथ दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में गिने जाते हैं।

श्रीलंका के दिग्गज सनथ जयसूर्या ने भी अपने

करियर की शुरुआत एक स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी और निचले क्रम में वह केवल तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। सन 1989 में डेब्यू के बाद कई सालों तक वह सातवें या आठवें नंबर पर आते थे और टीम में उनका मुख्य काम कसी हुई गेंदबाजी कर रन रोकना और विकेट लेना था पर साल 1995–96 के दौरान श्रीलंकाई टीम प्रबंधन और कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने उन्हें वनडे में ओपनिंग करने भेजा . यहीं से जयसूर्या एक आक्रमक सलामी बल्लेबाज के रूप में उभरकर सामने आए।

इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाने वाले केविन पीटरसन ने अपने करियर की शुरुआत एक ऑफ–स्पिनर के तौर पर की थी, जो निचले क्रम के बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरते थे। बाद में काउंटी

क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने के बाद 2004–05 में उन्हें इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में मध्यक्रम के प्रमुख बल्लेबाज के रूप में चुना गया।, उसके बाद पीटरसन ने कई रिकार्ड बनाये। वहीं इस सूची में भारतीय टीम के आक्रमक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा भी हैं। रोहित अपने स्कूल के दिनों में एक ऑफ–स्पिनर के तौर पर खेलते थे। उनके कोच दिनेश लाड ने उनके अंदर बल्लेबाजी की ऐसी प्रतिभा देखी कि उन्होंने रोहित को गेंदबाजी छोड़कर पूरी तरह बल्लेबाजी पर ध्यान लगाने की सलाह दी हालांकि, उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत एक मध्य क्रम बल्लेबाज के रूप में हुई थी, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रहा।

बीसीसीआई ने मुथूट फिनकोर्फ के साथ शुरु किया भारतीय क्रिकेट का नया अध्याय

तिरुवनंतपुरम : मुथूट फिनकोर्फ

लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेट में बड़ा कदम रखते हुए भारत में खेले जाने वाले घरेलू क्रिकेट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है।यह साझेदारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ कंपनी के जुड़ाव को और व्यापक बनाती है। इस करार के तहत मुथुट फिनकोर्फ भारत में होने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों और प्रमुख घरेलू प्रतियोगिताओं से जुड़ेगा। इसमें पुरुष और महिला सीनियर राष्ट्रीय टीमों के अलावा इंडिया–ए. इंडिया–बी. अंडर–19 टीमें तथा अन्य नामित टीमों के मुकाबले शामिल हैं।

कारोबार

अमेजन, फ्लिपकार्ट पर 10–10 लाख व जियोमार्ट पर पांच लाख का जुर्माना, सीसीपीए ने की कार्रवाई

नई दिल्ली। केद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अमेजन व फ्लिपकार्ट पर 10-10 लाख रुपये व जियोमार्ट पर पांच लाख रुपये का जुमाना लगाया है। तीनों ई- कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर साइबलोलिओन हर्बिसाइड नामक बिना पंजीयन वाले कृषि- रसायन उत्पाद को बेचने और उसका विज्ञापन करने का आरोप है।

22 सितंबर के एक अलग आदेश में उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने तीनों ई-कॉमर्स कंपनियों को उस उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन तुरंत रोकने का निर्देश दिया है जिसे उसके एक्टिव इंग्रीडिएंट के रसायन नाम या उसके कंपोजिशन का खुलासा किए बिना बेचा जा रहा था। सीसीपीए ने इन प्लेटफॉर्म्स को ऐसे उत्पाद की लिस्टिंग रोकने के लिए सेल्फ-ऑडिट करने का भी निर्देश दिया जो मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते हैं या उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। नियामक ने तीन प्लेटफॉर्म से 15 दिनों के भीतर

अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा है।

दरअसल, सीसीपीए को केद्रीय कृषि मंत्रालय से मिली एक शिकायत के बाद यह जांच शुरू हुई। इसे मूल रूप से क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआई) ने दर्ज कराया था। जांच के दौरान कृषि मंत्रालय ने सीसीपीए को बताया कि साइबलोलिसिनोन नाम का कोई भी रसायन कीटनाशक अधिनियम-1968 की अनुसूची में शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि इस उत्पाद की बिक्री और मार्केटिंग में कानून के तहत जरूरी सुरक्षा, बायो-एफिकेसी, गुणवत्ता और कानूनी जांच को नजर अंदाज किया गया। सीसीपीए ने पाया कि मार्केटप्लेस ने उत्पाद की लिस्टिंग को लाइव करने से पहले उसके रेगुलेटरी स्टेटस की पर्याप्त स्वतंत्र जांच नहीं की थी

अनुसंधान व उससे जुड़े उपकरणों से भी हटाएं जीएसटी: हर्ष गोयनका

उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पोस्ट में जीएसटी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी है कि बीसीसीआई को टैक्स में राहत मिलती है। वह प्रोत्साहन का हकदार है। लेकिन शोध प्रयोगशालाओं को



आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर पर क्यों टैक्स चुकाना पड़ता है? अनुसंधान और विकास को भी जीएसटी से मुक्त

कर भारत के भविष्य के निर्माण में मदद की जाए।

टाटा की एरिस कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च, शुरुआती कीमत 5.29 लाख

टाटा कार्स ने एरिस कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च की है। इसे विशेष रूप से व्यक्तिगत कार खरीदारों के लिए तैयार किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये है। यह सेडान पेट्रोल और आईसीएनजी विकल्पों में उपलब्ध होगी। ग्राहकों को इसमें एएमटी सुविधा भी मिलेगी। एरिस सभी डीलरशिप पर उपलब्ध है। पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये और आईसीएनजी मॉडल की 6.29 लाख रुपये है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी 11 अक्तूबर से शुरू होगी। शैलेश चंद्रा, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने कहा, एरिस हमारे ग्राहकों की प्रगति और व्यक्तित्व का प्रतीक है। इसे विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए तैयार किया गया है। एरिस में एलईडी हेडलैप, डीआरएल और अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें 26.03 सेंटीमीटर का एचडी टचस्क्रीन और वायरलेस कारप्ले/एंड्रॉइड

ऑटो जैसी तकनीक है। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, ईएसपी, एबीएस और 360 डिग्री केमरा शामिल हैं। यह केवल निजी खरीदारों के लिए उपलब्ध होगी, प्लटीट उपयोग के लिए नहीं।

व्यापार पर जेडब्ल्यूजी की बैठक: अक्तूबर में भारत आ सकता है बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल

बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल व्यापार संयुक्त कार्यबल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक के लिए अक्तूबर की शुरुआत में नई दिल्ली आ सकता है। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि बैठक में दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीके भी शामिल हैं। जेडब्ल्यूजी भारत और बांग्लादेश के लिए व्यापार से जुड़े मामलों पर चर्चा करने और द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों को सुलझाने का एक जरिया है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों पड़ोसी देश आर्थिक और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच जेडब्ल्यूजी की 15वीं बैठक 26 और 27 सितंबर, 2023 को ढाका में हुई थी।

अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया की तरह कैसे विकसित बनेगा भारत?

नई दिल्ली। वेदांता रिसोर्सज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने शनिवार को कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं का विरोध होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की तरह भारत को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए जमीन के नीचे मौजूद अपने खनिज संसाधनों का पूरा दोहन करने की जरूरत है।

अग्रवाल के वेदांता समूह ने ओडिशा में पहले ही एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है और वह रायगंडा में एक अन्य रिफाइनरी तथा दैंकनाल जिले में स्मेल्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए इननीही अतिरिक्त राशि का निवेश करने को तैयार है। अग्रवाल ने यह बात यहां मुख्यमंत्री मोहन वरमण माझी से मुलाकात के बाद कही। उन्होंने राज्य के पश्चिमी हिस्से में 1,000 बड़ वाला एक अस्पताल स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। कंपनी की कालाहांडी जिले के तालीगढ़ में रिफाइनरी है, जबकि झारसुगुड़ा जिले में एक स्मेल्टर और बिजली संयंत्र है, जो राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। रायगंडा जिले के रिसीमाली में बॉक्साइट खनन को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करने से जुड़े सवाल पर अग्रवाल ने कहा, "विरोध स्वाभाविक है। लोग विरोध करेंगे, लेकिन हम एक विकसित ओडिशा और विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। दो दशक पहले कुछ विदेशी तत्व हमारे सीधे-सादे लोगों को परियोजनाओं का विरोध करने के लिए भड़काते थे।

सीएम मोहन यादव ने अपने पैतृक मकान से की सड़क चौड़ीकरण की शुरुआत, गेती चलाकर दिया बड़ा संदेश

उज्जैन। सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के तहत शहर में सड़क चौड़ीकरण का काम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को अपने पैतृक मकान पर स्वयं गेती चलाकर सड़क चौड़ीकरण के लिए भवन हटाने की शुरुआत की। इसके साथ ही खजूर वाली मस्जिद से अब्दालपुरा, जीवाजीगंज थाना होते हुए गणेश चौक तक मार्ग के चौड़ीकरण की कार्यवाही प्रारंभ हो गई।

730 मीटर लंबे मार्ग का होगा चौड़ीकरण

करीब 730 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। मार्ग चौड़ीकरण एवं विकास कार्य के लिए राज्य शासन द्वारा करीब 9.80 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।



सिंहस्थ में सुगम यातायात के लिए महत्वपूर्ण कदम यह मार्ग शहर के महत्वपूर्ण

और व्यस्त संपर्क मार्गों में शामिल है। सिंहस्थ महापर्व के दौरान उज्जैन में श्रद्धालुओं और वाहनों

की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए मार्ग का चौड़ीकरण यातायात व्यवस्था को सुगम और



व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अपने घर से की त्याग की शुरुआत

मुख्यमंत्री द्वारा अपने पैतृक मकान से ही चौड़ीकरण की शुरुआत किए जाने को लेकर यह

भी संदेश गया कि सिंहस्थ की तैयारियों में विकास कार्यों के लिए आवश्यक त्याग की शुरुआत स्वयं अपने घर से की जा रही है। मार्ग चौड़ीकरण से क्षेत्र में आवागमन आसान होने के साथ ही सिंहस्थ के दौरान यातायात प्रबंधन को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

गुना कलेक्टर के नवाचार को मिली राष्ट्रीय पहचान



भोपाल। गुना जिले के राजस्व विभाग के नवाचार मोबाइल कोर्ट को यहां आयोजित 109वें स्कोच समिट 2026 में 'फाउंडेशन ऑफ इन्क्लूसिव ग्रोथ' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल को प्रदान किया गया, जिसे उनकी ओर से एसडीएम श्री अमित सोनी एवं तहसीलदार श्री देवदत्त गोलिया ने नई दिल्ली में ग्रहण किया। राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान जिला प्रशासन गुना की नवाचार आधारित एवं नागरिक-केंद्रित कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कलेक्टर श्री कन्याल के मार्गदर्शन में संचालित ह्यमोबाइल कोर्टह पहल का उद्देश्य प्रशासन को आमजन के द्वार तक पहुंचाकर भूमि संबंधी मामलों एवं विवादों का मौके पर ही त्वरित निराकरण करना है। इस पहल के माध्यम से अब तक 424 से अधिक मामलों का निराकरण किया जा चुका है। लंबे समय से लंबित विवादों को पक्षकारों की आपसी सहमति से सुलझाने की दशा में भी प्रभावी प्रयास किए गए हैं।

नरसिंहपुर में चलती कार में लगी भीषण आग

कुछ ही मिनटों में जलकर राख; झाड़वर ने कूदकर बचाई अपनी जान



नरसिंहपुर। स्टेशन गंज थाना अंतर्गत केंद्रीय जेल के पीछे अंडरपास के पास रविवार सुबह एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि समय रहते चालक ने

सूझबूझ दिखाते हुए कार को सड़क किनारे रोककर अपनी जान बचा ली।

चलती कार से उठा धुआं
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विपतपुरा निवासी डॉक्टर फरीद खान किसी आवश्यक कार्य से अपनी इंडिगो कार से शहर की

ओर आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंडरपास क्रॉस किया, कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए डॉक्टर फरीद ने तुरंत वाहन को सड़क किनारे खड़ा किया और सुरक्षित बाहर निकल आए।

आंखों के सामने जलती रही गाड़ी

बाहर निकलते ही कार में आग की लपटें तेजी से भड़क उठीं और कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। चालक अपनी आंखों के सामने अपनी कार को जलता हुआ देखता रहा, जिससे मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।

पुलिस और दमकल ने पाया काबू

घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन गंज थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया, तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

10 से 12 वर्षों का समयकाल बड़ा नहीं, लेकिन पीएम श्री मोदी ने आर्थिक ग्रांथ बढ़ाकर विकास के पहिये को गति दी

प्रदेश में पानी पर भी बिजली और पानी से भी एनर्जी स्रोत मजबूत हुए: मुख्यमंत्री डॉ. यादव



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित हिंदू इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में उद्योगपतियों को प्रदेश की उद्योग नीति और औद्योगिक विकास के प्रति शासन की प्रतिबद्धता से अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश आज उन क्षेत्रों में अग्रणी है, जो उद्योगों के लिए सबसे आवश्यक

और महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सरलस बिजली के साथ पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी पर सोलर पैनल से भी बिजली बनाई जा रही है। साथ ही पानी से एनर्जी के भी स्रोत मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के नए सेक्टर पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसमें

धार्मिक पर्यटन के साथ मेडिकल टूरिज्म भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार शाम होटल शेरटन, इंदौर में हिंदू इकोनॉमिक फोरम के इंदौर चैप्टर के शुभारंभ कार्यक्रम में

ह्यअर्थ अभ्युदयह विषय पर मुख्य संबोधन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2002-03 में मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगभग 11 हजार रुपये हुआ करती थी। वर्ष 2022 तक यह बढ़कर 1 लाख 40 हजार रुपये और वर्ष 2026 में 1 लाख 67 हजार रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि 10 से 12 वर्षों का

समयकाल बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की आर्थिक ग्रोथ बढ़ाकर विकास के पहिये को गति देने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अब तक हुए एमओयू को जमीन पर उतारने में सफलता मिल रही है। शासन की मंशा प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की है। मध्यप्रदेश में उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री वी. अनंता नागेश्वरन ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में देश की विकास दर 7.8 प्रतिशत है और आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत का विदेशों के साथ व्यापार लगातार बढ़ रहा है। कार्यक्रम में फोरम के प्रमुख

विज्ञानान्द ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बताया गया कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के अब तक तीन आयोजन देश-विदेश में हो चुके हैं। पहला आयोजन वर्ष 2014 में नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद वर्ष 2018 में अमेरिका के शिकागो शहर में और वर्ष 2023 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन हुआ। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का चौथा आयोजन आगामी 18 से 20 दिसंबर 2026 तक मुंबई में होगा। कार्यक्रम में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के कार्यक्रमों पर आधारित वृत्तचित्र भी दिखाया गया।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, विधायक श्री गोलू शुक्ला, श्री सुमित मिश्रा, संभागायुक्त श्री भास्कर लाक्षाकार, पुलिस आयुक्त श्री संतोष सिंह, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर श्री रिकेश वैश्य सहित बड़ी संख्या में उद्यमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।



भोपाल में शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना आज से शुरू

भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समेत तीन प्रमुख मांगों को लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने रविवार से राजधानी के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर रहा है। मोर्चे ने भोपाल में धरने को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने की रूपरेखा बनाई है। रविवार से अलग-अलग संभागों के शिक्षक इसमें शामिल होंगे।

समाधान नहीं निकलने पर आगे भी जारी रहेगा आंदोलन
दो अक्टूबर को विशेष उपवास कार्यक्रम और तीन अक्टूबर तक

विभिन्न संभागों की भागीदारी का कार्यक्रम है। मोर्चे ने मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कर तीनों मांगों पर सीधी चर्चा की मांग की है। संगठन का कहना है कि सरकार से समाधान नहीं होने की स्थिति में आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांग टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करना, प्रथम नियुक्ति की तारीख से सेवा अवधि और वरिष्ठता की गणना करने की है, ताकि प्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, पेंशन सहित सेवानिवृत्ति का लाभ मिल सके और ई-अटेंडेंस व्यवस्था समाप्त करने की है।

रीवा कलेक्टर जिस बस में बैठकर कार्यक्रम में पहुंचे, बिना फिटनेस, परमिट-बीमा के निकली; जांच के बाद सीज



की पुष्टि

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कलेक्टर ने परिवहन विभाग और एसडीएम को बुलाकर बस की जांच करवाई। जांच में अनियमितता की पुष्टि होते ही उन्होंने बस को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया और आरटीओ को फिटनेस रद्द करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर की सख्त चेतावनी

कलेक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि नियम सभी के लिए समान हैं। यदि सरकारी कार्यक्रम में ही बिना फिटनेस की बसें चलेगीं, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? उन्होंने जिले के सभी बस संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना परमिट, फिटनेस और बीमा के कोई भी बस सड़क पर न चलाए, अन्यथा ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित



भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2026 को किया जाना प्रस्तावित है। प्रदर्शनी की तैयारियों को लेकर पुलिस मुख्यालय, भोपाल के कॉन्फ्रेंस हॉल में विशेष पुलिस महानिदेशक श्री पंकज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीआईजी श्री साकेत प्रकाश पांडे, डीआईजी डॉ. विनीत कपूर पीएसओ टू डीजीपी, डीआईजी (उत्कृ) श्री प्रशांत खरे, डायरेक्टर रक्षक श्री राहुल कुमार लोढा, रक्षक के जॉइंट डायरेक्टर सहित जेल, अभियोजन, स्वास्थ्य, पर्यटन सहित विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदर्शनी की रूपरेखा, विभिन्न विभागों की सहभागिता तथा अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य आम नागरिकों को नवीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों तथा अपराध की घटना से लेकर न्याय मिलने तक की पूरी प्रक्रिया को सरल, सहज एवं रोचक तरीके से समझाना है। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित व्यवस्थाओं, तकनीक, नवाचारों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में पुलिस की कार्यप्रणाली को चरणबद्ध तरीके से दर्शाया जाएगा। इसमें थाने में अथवा राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 में सूचना प्राप्त होने, घटनास्थल पर पुलिस एवं एफएसएल टीम के पहुंचने, साक्ष्य संकलन एवं वैज्ञानिक विवेचना, पुलिस थाने में प्रकरण की कार्यवाही, सीसीटीएमएस, मालखाना एवं अन्य डिजिटल व्यवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

भेड़ाघाट में बनेगा विश्वस्तरीय जियोलॉजिकल पार्क और म्यूजियम

भोपाल। जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट-लम्हेटाघाट में देश का पहला विश्वस्तरीय जियोलॉजिकल म्यूजियम तथा पर्यटक सुविधाएं विकसित करने की 87 करोड़ रुपये की परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। परियोजना स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के माध्यम से लगभग 12 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएगी।

यह स्वीकृति लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह की करीब ढाई वर्षों से जारी सतत पहल का परिणाम है। श्री सिंह ने परियोजना की परिकल्पना को ठोस स्वरूप देने, प्रस्ताव तैयार कराने, संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए। परियोजना की मंजूरी से जबलपुर के पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा व्यापार के अवसर बढ़ेंगे।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने 18 जनवरी 2024 को मंत्रालय में जियो पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और डिजाइन का प्रस्तुतिकरण देखा था। उन्होंने परियोजना के प्रत्येक निर्माण को प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप करने,

संग्रहालय को आकर्षक और शिक्षाप्रद बनाने तथा लम्हेटा फॉर्मेशन, रानी दुर्गावती और जबलपुर की भू-संस्कृति को इसमें प्रमुखता से शामिल करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने प्रकृति अनुभव आधारित पर्यटन, नेचर स्ट्रे और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया था।

मंत्री श्री सिंह परियोजना की प्रगति और स्वीकृति की प्रक्रिया का लगातार अनुसरण करते रहे। उनके प्रयासों से तैयार प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा गया और अब इसे स्वीकृति मिली है। इस परियोजना को शहर की प्राकृतिक विरासत, विज्ञान शिक्षा और पर्यटन अर्थव्यवस्था से जुड़ी दीर्घकालीन जरूरत के रूप में आगे बढ़ाया। मंत्री श्री सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र शेखावत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भेड़ाघाट जबलपुर के साथ पूरे मध्यप्रदेश की पहचान है। यहां की संगमरमर की चट्टानें, धुआंधार जलप्रपात और नर्मदा नदी देश-दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। जियोलॉजिकल पार्क और म्यूजियम इस पहचान को नया विस्तार देगा।